(i) Most of the requirements of Operation Flood II for dairy equipment were to be met by utilisation of the funds available from World Bank for which the international competitive bidding procedure has to be followed by the I.D.C. as purchaser. This procedure would have come in the way of obtaining equipment from the proposed unit had it been set up under the I.D.C.

(ii) The Committee on Public Undertakings (1975-76) in its 83rd Report had also expressed the view that before setting up a new unit in the Public Sector for manufacture of dairy equipment, the possibilities of existing Public Sector units like H.M.T. manufacturing dairy equipment may be explored; and

(iii) The H.M.T. which is better equipped to undertake manufacture of machinery also indicated the inclination to diversify its manufacturing activities to include dairy equipment.

The Ministry of industry with the approval of Ministry of Finance has since entrusted the project to H.M.T.

अकाल से प्रभावित राज्यों को वित्तीय राहत देने के लिये मानदण्ड

4015. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अकाल से प्रभावित विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने में किसी मानदंड का पालन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों को ज्यादा और कुछ को कम सहायता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को दी गई सहायता दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) क्या अकाल से प्रभावित लोगों तथा उनके सामुदायिक स्तर जैसी बातों को उक्त धनराशि आवंटित करते समय उक्त प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा गया था ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ग). सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने के लिए किए जाने वाले व्यय की वित्तीय व्यवस्था करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के लिए वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर सिफारिश की गई व्यवस्था तथा नीतियों के अनुसार एक समान तथा उद्देश्यपूर्ण मानदंड अपनाती है । प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता की राशि का निर्धारण प्रत्येक मामले में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय दलों तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा आंकलित खर्च के आधार पर किया जाता है । राहत के लिए दी जाने वाली सहायता का स्वरूप व उसकी मात्रा का निर्धारण करते समय प्रभावित हुई आबादी, विशेषतौर से छोटे व सीमात कृषकों भूमिहीन श्रमिकों तथा राहत की जरूरत वाले अन्य निर्धनवर्गों को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Fishing Harbour in Kerala Coast

4016. SHRI A. A. RAHIM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of development schemes for fishing harbour in Kerala Coast; and

(b) whether any fishing harbour Development Scheme is being thought of with a view to assist the fishing industry?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) A deep sea fishing harbour was approved for Cochin. A major portion of the work has been completed. Under minor fishing harbours scheme and the scheme for provision of landing and berthing facilities, works have been executed at Vizhinjom (Phase I), Ponnani, Baliapatnam, Cannanore, Beypore and Kasargode.

(b) Schemes for development of fishing harbours have been prepared

for Neendakara, Vizhinjom (Phase II), Cheruvathur and Neeleswaram. In the case of Neendakara appraisal has been completed and the other three are under appraisal.

Water Salinity threat in Orissa and West Bengal

4017. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Orrissa and West Bengal are facing water salinity threat;

(b) whether it is also a fact that due to heavy silting in river Hooghly, formation of sweet acquifers is hindered;

(c) whether deep drilling beyond the prescribed limits is responsible in Orissa which makes this underground water saline; and

(d) if so, what remedial steps are being taken to deal with the issue?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) Certain pockets in the coastal areas of Balasore, Cuttack and Puri Districts in Orissa and coastal areas of Midnapore and 24-Parganas Districts of West Bengal are facing a salinity problem.

(b) Silting is one of the factors responsible for reducing the flow of water in the river Hooghly due to which the static ground water reservoir in the acquifers in the riverine tract are being affected.

(c) In some deep wells in the coastal areas of the Orissa State, drilled by C.G.W.B., the water is reported to have turned saline. The possible causes are under investigation.

(d) Remedial measures will be suggested after the causes for salinity are known through investigations.

उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में नलकूपों के लिए विश्व बैंक ऋण

4018. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय नलकूपों के लिए विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का नाम जोड़ने के रास्ते में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ; और

(ख) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) (क) उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 500 नलकूपों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण सम्बन्धी करार को अंतिम रूप दे दिया गया है । सीतापुर जिले को इस करार में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सार्वजनिक नलकूप प्रणाली की तकनीकी और परिचालन सम्बन्धी सुधारों के सापेक्ष्य गुणों का प्रदर्शन और मूल्यांकन किया जाये । यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में से, राज्य की कृषि जलवायु सम्बन्धी समग्र स्थितियों वाले केवल 12 जिलों में ही क्रियान्वित की जायेगी । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए राज्य के पश्चिमी केन्द्रीय और पूर्वी हिस्सों से बराबर-बराबर 12 जिले चुने गए हैं तथा इसी तरह नलकूपों की संख्या भी बांटी गई है । ये जिले नीचे दिए गए हैं :—

क्षेत्र	जिला	नलकूपों की संख्या
पश्चिमी	सहारनपुर	45
	अलीगढ़	40
	इटावा	40
	मैनपुरी	40
केन्द्रीय	लखनऊ	40
	लखीमपुर	40
	हरदोई	45
	फैजाबाद	45
पूर्वी	आजमगढ	40
	वाराणसी	40
	गाजीपुर	40
	इलाहबाद	45